

श्री नरेश अग्रवाल: *

MR. CHAIRMAN: Please. This will not go on record. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: *

MR. CHAIRMAN: From the Chair, in an unusual manner, I made a suggestion; first, let the Government discuss it and, then, come back to the House, and then, you can have your say. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: *

श्री सभापति: यह विपक्ष का, स्वपक्ष का, सत्तातट्ट पार्टी का सवाल नहीं है। ...(व्यवधान)... Please don't make such comments. आप बैठिए, प्लीज। आप कृपया बैठिए।

This morning, Shri B. K. Hariprasad met me personally and said what happened yesterday was on the spur of the moment and that he did not mean any disrespect to the Chair. He also said that he holds the office of the hon. Chairman in high esteem. In view of this, I have decided to treat the matter as closed.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need for a strict law to check Cyber Crime

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): सर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, जो आज आपने मुझे अवसर दिया है।

महोदय, 'साइबर क्राइम' एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए एक वरदान है। ...(प्लीज)... इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, व्हाट्सएप तथा अन्य कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। परन्तु यह जो ब्लेसिंग है, यह जो वरदान है, इस पर साइबर क्राइम ने ग्रहण लगा दिया है।

सर, साइबर क्राइम एक ऐसा दीमक है, जो हमारी व्यवस्था को चाट रहा है। मैं तो यह रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि साइबर क्राइम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक सख्त कानून लाया जाये। मेरा कहना है कि better prevent and prepare than repent and repair. मैं आभारी हूँ, मैं तो प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यह जो टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे करप्शन के ऊपर सीधी चोट की है, चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो या 'जन-धन योजना' हो। यह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसने हम सबको लोगों के साथ कनेक्ट किया है।

इसीलिए कनेक्ट किया है और आज सोशल मीडिया जो है, वह बड़ा महत्वपूर्ण मीडिया है, जिससे हम कुछ सेकेंड्स में ही सारे देश के सवा सौ करोड़ देशवासियों से कनेक्ट हो जाते हैं।

* Not recorded.

[श्री श्वेत मलिक]

मैं इसके लिए एनडीए की सरकार को बहुत धन्यवाद करूंगा, पर यह जो साइबर क्राइम है, जैसा मैंने कहा कि यह एक ग्रहण बन कर इन उपलब्धियों पर खड़ा है। हमें information technology से जो economic globalization की blessing मिली है, उससे हम grow कर रहे हैं, लेकिन इस साइबर क्राइम के कारण आम जनता कष्ट में है, जिसमें सबसे पहले terrorism है। Cyber terrorism कनेक्ट करने का आसान रास्ता है। जो terrorists हैं, वे निर्भीक होकर इसके माध्यम से लोगों को आतंकित भी करते हैं और लोगों को misguide भी करते हैं। इसके माध्यम से वे अपना कुसंदेश लोगों तक पहुंचाते हैं।

सर, ऐसे ही बिजनेस में जो वेबसाइट्स हैक होती हैं, इन हैक की हुई वेबसाइट्स से वे लाभ उठाते हैं और बिजनेसमैन के साथ लाखों-करोड़ों रुपए का धोखा कर देते हैं। जो हमारी माताएं-बहनें हैं, उनके खिलाफ भी इस साइबर क्राइम के थ्रू बहुत जबर्दस्त क्राइम हो रहा है और जो साइबर बुलिंग है, उससे कोई भी संदेश कहीं भी पहुंच जाता है। सर, मैं आपके माध्यम से इस हाउस से डिमांड करूंगा कि सरकार के माध्यम से इस साइबर क्राइम को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि आम आदमी निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके।

SHRI AMAR SHANKAR SABLE (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by hon. Member.

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री सुरेंद्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री सभापति: ठीक तरह से जवाब देना कहना ठीक है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देना कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना अच्छा होगा।

Non-utilization of funds under the Namami-Gange Project

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): सर, जहां आज केंद्र की सरकार है, वहां किसानों को उनके उत्पादों के मूल्य न मिलने के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वहीं राष्ट्रीय मिशन में सम्मिलित 'नमामि गंगे परियोजना' की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए आवंटित 26 सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपयोग नहीं की गई है। 2017 तक इसका उपयोग कर लिया जाना था, पर 2017 की समाप्ति के बाद भी 26 परियोजनाएं, जो गंगा की सफाई से, गंगा की स्वच्छता से जुड़ी थीं, आज तक वे परियोजनाएं न तो बनी हैं और न जो रुपए इनके लिए आवंटित हैं, उनका उपयोग हुआ है। यह बात तो समझ में आती है कि सरकारें बनने के बाद जनता के साथ * करती रही हैं।...(व्यवधान)...

* Expunged as ordered by the Chair.